नव भारत 1934 से

मोदी और मैक्रों की दमदार दोस्ती

दोनों देश ऐसा हेलिकॉप्टर बनाएंगे, जो माउंट एवरेस्ट जैसी ऊंचाइयों तक उड़ान भरेगा

मुंबई, 17 फरवरी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने मुंबई में जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान मोदी ने कहा कि भारत और फ्रांस मिलकर भारत में ऐसे हेलिकॉप्टर का निर्माण करेंगे, जो माउंट एवरेस्ट जैसी ऊंचाइयों तक उड़ान भरेगा। मोदी ने फ्रांस को भारत का स्पेशल पार्टनर बताया और कहा कि दोनों देशों ने अपने रिश्तों को 'स्पेशल ग्लोबल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप' लेवल तक अपग्रेड करने का फैसला किया है। मोदी के शासनकाल में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों की यह चौथी यात्रा दर्शाती है कि दोनों राष्ट्रध्यक्षों के बीच दोस्ती प्रगाढ़ है.

इसके बाद मैक्रों ने इंडिया-फ्रांस इनोवेशन फोरम को संबोधित करते हुए कहा दुनिया के कई बड़ी कपनियों के सीईओ भारतीय हैं।

उन्होंने कहा कि अल्फाबेट, माइक्रोसॉफ्ट, सीईओ, एडोबी और पालो आल्टो नेटवर्क्स के सीईओ भारतीय हैं। अब भारत लीडरशिप करने वाला देश बन गया है।

डिफेंस सेक्टर में फ्रांस, 'मेक इन इंडिया' का भरोसेमंद साथी है। उन्होंने कहा कि दोनों देश मिलकर नए जमाने के इंजन, मल्टी-रोल हेलिकॉप्टर, मॉर्डन फाइटर जेट्स और पनडुब्बियां बनाने पर काम कर रहे हैं। मैक्रों ने कहा कि यह सिर्फ रक्षा सौदों तक सीमित बात नहीं है, बल्कि यह दो बड़े देशों की मजबूत साझेदारी है। उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस जमीन, समुद्र और आसमान हर सेक्टर में अपनी इच्छा और भरोसे के साथ एक-दूसरे के साथ खड़े हैं।

फैक्ट फाइल

- भारत को 24 सुपर राफेल फाइटर जेट मिलेंगे. इन एडवांस्ड जेट को एफ-5 वर्जन कहा जा रहा है, जिन्हें फ्रांस की कंपनी दसॉ एविएशन बना रही है।
- भारत में बनेंगे 96 राफेल फाइटर जेट
- भारत पहले ही खरीद चुका है 36 राफेल जेट एफ

मैक्रों ने की जॉगिंग

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों मंगलवार सुबह मुंबई की सड़कों पर जॉगिंग करते नजर आए। सोशल मीडिया पर उनके जॉगिंग के वीडियो शेयर किए गए थे। वे नीले रंग की शॉर्ट्स और टी-शर्ट पहनकर मुंबई में दौड़ते नजर आए। उनके साथ उनकी सुरक्षा टीम और भारतीय सुरक्षा अधिकारी मौजूद थे। मुंबई पुलिस के जवान भी सड़क पर तैनात थे।

क्या होती है स्पेशल ग्लोबल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप

'स्पेशल ग्लोबल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप' का मतलब है कि दोनों देश सिर्फ व्यापार या हथियारों की खरीद-फरोख्त तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि सुरक्षा, तकनीक, अंतरिक्ष, समुद्री इलाकों की सुरक्षा और बड़े वैश्विक मुद्दों पर साथ मिलकर काम करेंगे। इससे पहले दोनों देशों के बीच संबंध स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप लेवल के थे। यह पार्टनरशिप साल 1998 में शुरू हुई थी।

एआई समिट का दूसरा दिन

रोबोट ने लगाए ठुमके

नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के दूसरे दिन कुछ अलग ही नजारा देखने को मिला. प्रदर्शनी क्षेत्र में लगाए गए एक एआई ह्यूमनॉइड रोबोट ने दर्शकों को अपने अनोखे डांस से इम्प्रेस किया. यह रोबोट संगीत की धुन पर बिल्कुल इंसानों जैसा नाचता दिखा. जैसे ही रोबोट ने कदम थिरकाने शुरू किए, लोगों की भीड़ उसके आसपास जुट गई. समिट में एआई और रोबोटिक्स जैसे क्षेत्रों के जुड़ी कई कंपनियों ने अपने प्रोडक्ट्स पेश किए. इस दौरान टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का फिजिकल एआई रोबोडॉग भी आकर्षण का केंद्र रहा. कंपनी ने बताया कि चार पैरों वाला यह रोबोडॉग किसी जानवर के जैसे चलता है और एक इंजीनियर के जैसे प्रॉब्लम को सुलझा सकता है. इस रोबोडॉड का इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन साइट, वेयर हाउस और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में इस्तेमाल के लिए किया गया है.

देश में एआई में आएगा 200 अरब डॉलर का निवेश : अश्विनी वैष्णव

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में कहा कि आने वाले दो वर्षों में भारत में एआई क्षेत्र की पांचों परतों में 200 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का निवेश आने की उम्मीद है. जोखिम पूंजी कंपनियां गहन तकनीक स्टार्टअप्स और अनुप्रयोगों, अत्याधुनिक मॉडल्स पर शोध और बुनियादी ढांचा और ऊर्जा परतों में निवेश कर रही हैं. इस मौके पर केंद्रीय इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री जितिन प्रसाद भी मौजूद रहे.

अब टाटा बनाएगी देसी पांचवी जनरेशन फाइटर जेट

भारत ने पांचवीं पीढ़ी के देसी स्टेल्थ फाइटर जेट एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए बड़ा कदम उठाया है. रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने इस पांचवी जनरेशन जेन फाइटर जेट का प्रोटोटाइप डिजाइन करने के लिए तीन दावेदारों को शॉर्ट लिस्ट किया है. इनमें टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड सबसे बड़ी दावेदार के तौर पर उभरी है, जबकि लार्सन एंड टुब्रो-भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का कंसोर्टियम और भारत फोर्ज डेटा पैटर्न्स का संयुक्त समूह शामिल है.

जीएसडीपी में 11.14 प्रतिशत की वृद्धि

14 हजार 926 रुपए एक साल में बढ़ी प्रति व्यक्ति आय

16 69,750 करोड़ जीएसडीपी प्रचलित मूल्यों पर अनुमानित

भोपाल, 17 फरवरी. मध्यप्रदेश में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए वार्षिक बजट पेश होने के एक दिन पहले मंगलवार को सामने आए आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार सकल राज्य घरेलू उत्पाद -जीएसडीपी- और प्रति व्यक्ति आय में जबर्दस्त बढ़ोतरी हुई है, जो राज्य की अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ होने की ओर संकेत करते हैं.

वर्ष 2025-26 के लिए पेश किए गए राज्य के आर्थिक सर्वेक्षण में यह तथ्य उभरकर सामने आए हैं. वित्त वर्ष 2025-26 (अग्रिम अनुमान) में प्रदेश का जीएसडीपी प्रचलित मूल्यों पर 16,69,750 करोड़ अनुमानित है, जो वित्त वर्ष 2024-25 (त्वरित अनुमान) के 15,02,428 करोड़ रुपयों की तुलना में 11.14 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है. इसी तरह वित्त वर्ष 2025-26 (अग्रिम अनुमान) में जीएसडीपी स्थिर (2011-12) मूल्यों पर 7,81,911 करोड़ अनुमानित है, जो वित्त वर्ष 2024-25 (त्वरित अनुमान) के 7,23,724 करोड़ की तुलना में 8.04 प्रतिशत की वास्तविक वृद्धि को प्रदर्शित करता है. सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2024-25 से वर्ष 2025-26 की अवधि के दौरान प्रदेश की प्रति व्यक्ति शुद्ध आय प्रचलित मूल्यों पर 1,54,124 से बढ़कर 1,69,050 हो गई. इस तरह एक वर्ष में ही इसमें 14 हजार 926 रुपए की बढ़ोतरी हुई है. जो कि प्रदेश के तेजी से बेहतर हो रही आर्थिक स्थिति का संकेत है. वर्ष 2025-26 (अग्रिम अनुमान) में सकल राज्य मूल्य वर्धन (जीएसवीए) की क्षेत्रीय संरचना प्रचलित मूल्य इस प्रकार रही. प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 43.09 प्रतिशत, द्वितीयक क्षेत्र का 19.79 प्रतिशत और तृतीयक क्षेत्र का 37.12 प्रतिशत रहा.

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट के परिप्रेक्ष्य में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में मध्यप्रदेश की अर्थव्यवस्था समावेशी विकास के साथ अत्यंत गतिशील अर्थव्यवस्था बन गई है. वित्तीय अनुशासन, पारदर्शी प्रशासन और दूरदर्शी नीतियों के साथ मध्यप्रदेश की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई है. आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार राज्य की अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध रूप से संतुलित और परिणामोन्मुखी है. सर्वेक्षण के मुताबिक वित्त वर्ष 2025-26 में प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत फसलों का सर्वाधिक योगदान 30.17 प्रतिशत रहा. इसके बाद पशुधन 7.22 प्रतिशत, वानिकी 2.13 प्रतिशत, मत्स्यपालन एवं जलीय कृषि 0.61 प्रतिशत तथा खनन एवं उत्खनन 2.96 प्रतिशत रहा.